P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अर्थव्यवस्था में तेजी से उभरती समस्या

इंदू भारती
कनिष्ठ व्याख्याता,
अर्थशास्त्र विभाग,
एजूकेशन डिपार्टमेण्ट,
पंचकुला, हरियाणा

सारांश

अर्थशोधन तेजी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिन्तनीय विषय हैं। अर्थशोधन (Money Laundering) U.S.A. में एक माफिया समूह के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। 80के दशक में अमेरिकाइस विषय में काफी चिंतित था। भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के लिए आज यह विषय एक ऐसी समस्या के रूप में उभरा हैं जिससे निपटने के लिए आर्थिक व कानूनी संस्थाए साथ मिल कर कार्य कर रही हैं परन्तु इसके बावजूद भी इससे निपटना टेढ़ी खीर बना हुआ हैं।1990 के दशक में ''हवाला कांड'', जिसमें अनेक बड़े नेताओं व हस्तियों के नाम शामिल थे, के बाद यह समस्या भारत में खुल कर सामने आई। परन्तु 21 वीं शताब्दी में बड़े–2 नाम व माफिया समूह के साथ छोटे–2 व्यापारी भी (Money Laundering) अर्थशोधन को सामान्य सी बात समझ कर धड़ल्ले से इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके सही रूप को समझ कर इसके समाधान के लिए बने एक्ट के साथ–2 आम जन को इसके प्रति जागरूक करना जरूरी हैं ताकि मिलकर इस समस्या का समाधान किया जा सके।

मुख्य शब्द : अर्थशोधन, हवाला, माफिया, PMLA, कालाधन,कर–चोरी।

प्रस्तावना

अर्थशोधन एक ऐसी प्रकिया है जिसके द्वारा अवैध रूप से कमाएँ गए या काले धन को कानूनी या वैध रूप दिया जाता है। मोटे शब्दों में काले धन को देकर सफेद करना ही अर्थशोधन (Money Laundering) हैं। भारत में अर्थशोधन की समस्या इतना गंभीर रूप धारण कर चुकी है कि इसके कारण एक समानान्तर अर्थव्यवस्था का जन्म हो गया हैं। हम कह सकते है कि अर्थव्यवस्था में गैर कानूनी तरीको से कमाएँ गए धन को इतनी चतुराई से शामिल कर दिया जाए कि उस धन के स्त्रोत का पता ही ना लगे और वो कानूनी या वैध मुद्रा में शामिल हो जाए तो वह अर्थशोधन ही हैं। इसमें हम उन सभी आपराधिक गतिविधियों को शामिल करते हैं जिससे आय का सृजन होता है। नशीली दवाएँ बेचना,कर चोरी, फर्जी फर्मे शुरू करना,भ्रष्टाचार,लेखांकन गडबड़ी व अन्य अनेक आपाराधिक धन कमाने की गतिविधियां, इसमें शामिल हैं। 1996 में अर्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया कि विश्व में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2 से 5 प्रतिशत हिस्सा काले धन को वैध बनाने में शामिल था। भारत में समय–2 पर काले धन से सम्बन्धित बनाई गई कमेटियों के अनुसार 2 से 12 प्रतिशत तक काला धन हो सकता है। भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ी धन–राशि हैं। यह राशि देखते ही देखते सफेद–धन यानी वैध मुद्रा में बदल जाती है। भारत में नवम्बर 2016 को हुई नोटबंदी भी Money Laundering की प्रक्रिया को रोक ना पाने के कारण असफल हो गई। अर्थशोधन एक लाईलाज बीमारी की तरह भारत की अर्थव्यवस्था में समा गई है और इसकी प्रक्रिया को गहराई से समझकर ही हम इसकीजड़ो को काट सकते है।

साहित्यावलोकन

Jeffrey Robinson ने अपनी पुस्तक The Launderymen – inside the world's third largest business में गंदी मुद्रा या अवैध मुद्रा को वैध बनाने पर तथा अवैध मुद्रा के स्त्रोतों पर विस्तार से लिखा।

Jeffery Robinson ने यहॉ जुर्म और आतंकवाद के वित पोषण से काला धन व धनशोधन के सम्बन्धों के बारे में गहराई से लिखा है। पुस्तक हमें कानूनी राजनैतिक व आर्थिक तंत्र किस प्रकार अर्थ–शोधन को प्रोत्साहित करता है इस बारे में बतलाती हैं।

Dr. Shamsuddin-commentary on the preventionof Money Laundering Act 2002- ने 2002 में बनाए गए अर्थशोधन को रोकने के कानून का विवेचन किया है।

Rajeev Babel- Prevention of Money Laundering in India and other countriesमें PMLA के साथ–साथ अर्थशोधन प्रक्रिया को रोकने में सहायक कानूनों का विश्लेषणात्मक विवेचन किया हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थशोधन एक बहुत तेजी से उभरती हुई समस्या हैं। दिन–प्रतिदिन समाचार पत्र पत्रिकाओं व समाचार tv चैनलो पर काले धन व मनी लॉन्ड्रिंगरॉकेट का पर्दाफाश किया जा रहा हैं। शोध–पत्र का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग (अर्थशोधन) की जरूरत प्रक्रिया तथा रोक के लिए बनाए गए नए कानूनों की प्रभावशीलता के अध्ययन के साथ समस्या का हल खोजने का प्रयास करना हैं।

अनुसंधान किया विधि

यह शोध पत्र विभिन्न अदालतों में धनशोधन से सम्बन्धित मुकदमों विश्वसनीय अखबार में छपने वाले समाचार तथा हरियाणा के विभिन्न जिलों के बारे में एकत्रित किए गए प्राथमिक आंकडों पर आधारित हैं।

1. Feb.2019 में आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में करीब 20 हजार करोड़रूपये का अर्थशोधन रैकेट पकड़ा। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने पुरानी दिल्ली में तीन समूहों को इसमें लिप्त पाया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नया बाजार इलाके में करीब 18 हजार करोड रूपये के फर्जी बिल पास किये। कई फर्जी इकाइयों का भी पदाफ फाश किया गया।
2. 2018व 2019 में भारत में आयकर विभाग के अनेक छापों में बेहद सगंठित मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का पता चला। यह तरीका कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। इसमें लोग बड़ी कम्पनियों के शेयरों को धोखाधड़ी के जरिए वर्षो से रखे गए पुराने शेयर बताकर बेच देते है। इस तरीके से ''लॉन्ग टर्म कैपिटल'' गेन्स का फर्जी दावा कर पैसे कमाए जाते हैं।
3. राबर्ट वाड्रा जो एक बहुत बड़े राजनैतिक घराने से सम्बन्ध रखते है के खिलाफ हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में व लदंन स्थित 12 ब्रायंस्टर स्कवायर में 19 लाख पांउड में सम्पति की खरीद में धनशोधन के आरोप है।

हालांकि ये आरोप अभी साबित नही हुए परन्तु अपने गृह–राज्य हरियाणा में किए सर्वे में पाया कि जमीन की खरीद–फरोख्त अर्थशोधन का एक मुख्य स्त्रोत हैं।

1. अखिलेश यादव–खनन घोटाले – अर्थशोधन केस में अदालत में केस चल रहा हैं।
2. नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन मामले में "आंतकी शब्बीर अहमद लोन" के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया हैं। ED ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत विदेशी नकदी जब्त की हैं। आंतक माफिया गिरोह व मनी लांड्रिग का सम्बन्ध बहुत गहरा हैं।
3. तेलगी घोटाला जो कि झूठे जाली STAMP PAPER से सम्बन्धित हैं अर्थशोधन का बड़ा खुलासा करता हैं।
4. सर्वविदित है कि किस प्रकार बॉलीवुडमें माफिया गिरोह द्वारा काले धन को सफेद किया जाता हैं। दाऊद का नाम फिल्म उद्योग से अक्सर जुड़ता रहता हैं। और इनके सम्बन्धों के सबूत भी जारी किए जाते हैं।
5. हरियाणा के हिसार,फतेहाबाद,सिरसा आदि जिलों में प्राथमिक सर्वे भी फर्जी फर्मो द्वारा मनी लान्ड्रिग प्रक्रिया की और सकेंत करता हैं। यहॉ मनी लांड्रिग का अन्य बड़ा स्त्रोत जमीन की खरीद व सोने की फर्जी ब्रिक्री (खासतौर पर नोटबंदी के समय)रहा।
6. अर्थशोधन रोकने में सहायक कानून व संधियॅा

भारत में अर्थशोधन को रोकने के लिए अनेक कानून बने हैं जिसमें PMLA 2002 जो January 2003 में लाया गया और 1st July 2005 से प्रभावी हुआ अत्यन्त महत्वपूर्ण Act हैं। इसके अतिरिक्त आयकर कानून -1961, COFEPOSA 1974, NDPSA 1985, बेनामी लेन–देन पाबन्दी-1988 और FEMA 2000 Act भी मनी लांन्ड्रिग रोकने में सहायक सिद्व होते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा या विदेशों में अर्थशोधन को रोकने के लिए भी कई प्रावधान किए गए है। इनमें वियना संधि, United Nations के द्वारा अर्थशोधन के विरूद्व चलाये विश्वस्तरीय अभियान तथा वितीय कार्रवाई कार्यदल एक अन्तरसरकारी संस्था आदि प्रमुख है। ये सभी मिलकर एकजुट होकर कार्य कर रहे है व समय–2 पर कानूनी प्रावधानों व अर्थशोधन रोकथाम करने वाली सस्थाओं में संशोधन व आधुनिकीकरण भी कर रहे है।

निष्कर्ष

संक्षेप में हम कह सकते है कि अर्थशोधन एक ऐसी समस्या है जो दिखने में इतनी गंभीर नही लगती परन्तु इसके प्रभाव इतने गभीर है कि अर्थव्यवस्था को खोखला कर दें। आम जन से लेकर प्रतिष्ठित, औद्योगिक, चलचित्र क्षेत्र भी इसकी गिरफ्त में हैं। इन्टरनेट के युग में इन अर्थशोधन प्रक्रियाओं को अंजाम देना और भी आसान हो गया हैं। दिन–प्रतिदिन मनी लॉन्डरिंग केंस के बड़े–2 घोटाले सामने आ रहे हैं–पाल पाबला मनी लॉन्डरिंग केस के बडे–2 घोटाले सामने आ रहे हैं– पाल पाबला मनी लॉन्डरिंग केस, गोतम खेतान अगस्टावैस्ट लैण्ड घोटाला, Seven Coal Scam आदि केस जो ED प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार के वित मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन विशेष वितीय जांच एजेन्सी है के द्वारा अदालतों में भेजे जा रहे हैं।

आम जन जाने अनजाने में इसे टैक्स से बचने की सामान्य प्रक्रिया समझ इसमें शामिल हो रहे है तो कुछ टैक्स की जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए इसमें शामिल हो रहे हैं एक छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योग पति तक इसकी गिरफ्त में हैं।

सुझाव

1. अर्थशोधन पर सभी देश समान रूप से चिन्तनीय हैं परन्तु भारत, चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता हैं कि इससे सख्ती से निपटा जाए परन्तु इसके लिए सम्पूर्ण विश्व को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। अनेक देशों में

वितीय गोपनीयता का प्रावधान इस संदर्भ में एक विशेष मुद्दा हैं। राज्य इस गोपनीयता के साथ समझौता करने के इच्छुक नहीं हैं। स्विस बैंक में भारत का जमा काला धन भारत के लिए हमेशा से एक चुनौती रहा हैं। बडे–बडे औधोगिक व राजनैतिक घरानों के नाम स्विस बैंक खातों में उछले हैं। ऐसे वितीय गोपनीयता के नियम व धन शोधन के ठिकाने बनने वाली वितीय सस्थाओं को ठीक तरह से नियमन करने की आवश्यकता हैं।

2. अर्थशोधन की समस्या से निपटने के लिए हमें देश में नशा जुआ, आंतक व माफिया के अपराधों पर भी कड़ी कार्यवाही करनी होगी। ये आपराधिक उघोग काले धन के अड्डे होते हैं और इनकी पहुँच अर्थशोधन गिरोह तक होती हैं।
3. सरकार को भी चाहिए कि वह आयकर, ब्रिक्री कर ,तथा अन्य कर की दरों को कम रखें व इन्हे भरने की प्रकिया को भी सरल रखें। उघोगों के लाइसैंस आदि औपचारिकताओं को इतना सरल बनाए कि एक पढ़ा–लिखा व्यक्ति भी कागजी कोकाम को आसानी से पूरा कर सकें।
4. आमजन में भी इस विषय में जागृति लाने के लिए अभियान चलाएँ और देश पर अर्थशोधन के पड़ने वाले प्रभावों से अवगत कराएँ। क्योंकि आम–जन को देश की अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले बुरे प्रभावों की जानकारी नहीं होतीं तथा वह इसमें अनजाने में शामिल हो जाता हैं। इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षित करके उनमें जागरूकता की भावना लाकर सामाजिक रूप से संगठित होकर इस वित्तीय अपराध को नियन्त्रित किया जा सकता हैं।
5. अर्थशोधन को रोकने के लिए बनाए गए कानून अधिक प्रभावी व एक–दूसरे विभाग में इन पर परस्पर एकजुटता होनी चाहिए जैसे यदि बैंक किसी अर्थशोधन मामले की पहचान करें तो आयकर विभाग व वित्तीय आपराधिक जॉच सस्था ED तथा अदालते उस पर पूर्ण मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करें। Money Laundering के अधिकांश केस सालों तक लटके रहते हैं व अपराधी जमानत पर चलता रहता हैं और अन्त में सबूतों व साक्ष्यों को प्रभावित कर केस को कमजोर कर केस को कमजोर कर देता हैं।
6. प्रभावी धन–शोधन के उपायों को लागू करने में केन्द्र व राज्य को एकजुट होना होगा। इन कानूनों को लागू करने के लिए केन्द्रीय ही नहीं बल्कि राज्य की संस्थाएँ भी पूर्ण सहयोग करें व दोनों की इसमें समान जवाबदेहिता हो।

अतः संक्षेप में कह सकते है कि अर्थ–शोधन एक कैंसर की बीमारी की तरह अर्थव्यवस्था को खा जाए इससे पहले आम जन से सरकार तक वित्तीय विभाग से लेकर अदालतों तक सभी मिलकर इस ओर ध्यान दें व विदेशों का भी सहयोग लें व दें।

सदर्भ ग्रंथ सूची

1. *The Prevention of Money Laundering Bill (2002) And Amendment (2011)*
2. *David A chaikin – "Investigating Criminal & Corporate Money Trails" In The Money Laundering and Cash Transaction Reporting.*
3. *अब्दुल करीम तेलगी और सोहेल खान V/S Union of India केस Through CBI 2014 (2) JLJ-136.*
4. *Enforcement Directorate (1995) official Website.*
5. *Foreign Exchange Management Act 1999.*
6. *Jeffery Robinson's Book–The Laundrymen-inside the world's third largest business.*
7. *Dr. Shansuddin's Book-Commentary on the Prevention of Money Laundering Act 2002.*
8. *Rajeev Balel's Book –Prevention of Money Laundering In India and other*